



संचार मंत्री, दूरसंचार विभाग का संदेश

अक्टूबर 2026 संस्करण

विषय: सीमाओं से परे विस्तार: भारत का डिजिटल अवसर

नमस्कार!

किसी राष्ट्र की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वह अपने देश में क्या विकसित करता है, बल्कि इससे भी होती है कि वह विश्व को क्या योगदान देता है। इस महीने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दस संस्करण पूरे होने के साथ, दूरसंचार विभाग कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी और विश्वास से जुड़े वैश्विक विमर्श में एक प्रमुख भूमिका में उभरा और इस मंच पर भारत की आवाज़ को वैश्विक स्तर पर विश्वास के साथ सुना भी गया।

दसवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में किया। इस आयोजन से पहले जीएसएमए बोर्ड के साथ प्रधानमंत्री की बैठक ने वैश्विक मोबाइल इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। इस आयोजन में नीति-निर्माताओं, प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, दूरसंचार ऑपरेटर्स, स्टार्टअप, निवेशकों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इसके अंतर्गत दूरसंचार विभाग ने विभिन्न राज्यों के दूर संचार मंत्रियों और सचिवों के साथ एक गोलमेज बैठक आयोजित की। साथ ही, "सीमाओं से परे विस्तार: अगले एक अरब डिजिटल कनेक्शनों में निवेश" विषय पर एक मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के गोलमेज सम्मेलन में दूरसंचार क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा की गई। इस दौरान वैश्विक 6जी पेटेंट और मानकों में भारत की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी दोहराई गई।

इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दिशा देने के लिए तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भारत 6जी संगोष्ठी में एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीन दिनों तक चले इस आयोजन में वैश्विक दूरसंचार विशेषज्ञों, मानक निर्धारण संस्थाओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया तथा आईएमटी-2030 और उससे आगे की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के विकास की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया। भारत ने सीमा-पार दूरसंचार धोखाधड़ी से निपटने के लिए संयुक्त परीक्षणों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि सीमाओं से परे फैलने वाले खतरों का प्रभावी मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। मीडिया से बातचीत के दौरान मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास और निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार और उद्योग जगत को मिलकर काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ हमारी साझेदारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। एआई फॉर गुड लैब वर्कशॉप और एआई फॉर गुड बिल्ड-ए-थॉन 5.0 के माध्यम से शोधकर्ताओं और युवा नवप्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया, जहां उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एजेंटिक एआई आधारित समाधान विकसित करने पर कार्य किया। 5जी उपयोग-आधारित प्रयोगशालाओं पर आयोजित कार्यशाला ने अकादमिक अनुसंधान और वास्तविक जीवन में प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक उपयोग के बीच सेतु को सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त, आईआईटी दिल्ली स्थित आई-हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स के सहयोग से आयोजित रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 ने युवा प्रतिभाओं को अपनी नवाचार क्षमता प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर कृषि-खाद्य प्रणालियों में एआई के उपयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल की दूसरी बैठक की मेजबानी की और विश्व मानक दिवस 2026 भी मनाया गया।

स्वदेशी क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। इसी क्रम में, सी-डॉट ने अपने छठे उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल शैक्षणिक संस्थानों की विशेषज्ञता और दूरसंचार अनुसंधान के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, ग्वालियर में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान दे रहा है और ग्वालियर को दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी सहायक बन रहा है।

कनेक्टिविटी देश के प्रत्येक गांव तक पहुंचनी चाहिए। इसी दिशा में, राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन को गति देने के लिए डिजिटल भारत निधि, दूरसंचार विभाग, महाराष्ट्र सरकार, एमडीआईएल, बीएसएनएल और महाआईटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहल ग्रामीण महाराष्ट्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार को गति देगी और सहकारी संघवाद की भावना को धरातल पर उतारने का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगी। इसी बीच, मई 2023 में शुरू किए गए संचार साथी पोर्टल पर अब तक 30 करोड़ से अधिक विजिट दर्ज किए जा चुके हैं। यह नागरिकों के बीच इस प्लेटफॉर्म की बढ़ती स्वीकार्यता और विश्वास को दर्शाता है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक संदिग्ध संचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जांच कर सकते हैं तथा खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक कराने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। दूरसंचार विभाग खोए और चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की बरामदगी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, पुलिस जिलों और पुलिस थानों को सम्मानित करेगा।

सुशासन की शुरुआत घर से होती है। 'स्वच्छता ही सेवा 2026' अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत' की थीम पर दूरसंचार विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, क्षेत्रीय इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता गतिविधियों में भाग लिया। अक्टूबर तक चलने वाले विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने और अभिलेखों के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। टीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार को 43.86 करोड़ रुपये का लाभांश दिया। राष्ट्रीय संचार अकादमी-वित्त में आयोजित विशेष फाउंडेशन कोर्स 2026 में अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं के 11 संवर्गों से आए कुल 116 अधिकारी प्रशिक्षुओं का स्वागत किया गया। समग्र रूप से, यह घटनाक्रम एक ही दृढ़ विश्वास व्यक्त करत है: भारत की डिजिटल यात्रा की कोई सीमा नहीं है और इसकी महत्वाकांक्षा दुनिया भर में इसके संस्थानों, इसके नवप्रवर्तकों और इसके भागीदारों से मेल खाती है। भारत के लिए विकास का दायरा केवल विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करना और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के दम पर वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाना है।

जय हिंद

आपका,

ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया

संचार मंत्री, भारत सरकार